Title: Need to relax the Central Government recovery for paddy in Uttar pradesh or give speical package to save the farmers.

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उत्तरप्रदेश) : उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 510 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है परन्तु विभिन्न राज्यों में समर्थन मूल्य पर धान की खरीद न होने के कारण किसानों का धान 300-350 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जा रहा है जिससे किसान के पैदावार की लागत भी नहीं निकल रही है।

उपाध्यक्ष महोदयः आज इस विाय पर 193 के अन्तर्गत चर्चा है। आप संक्षेप में अपनी बात कहें।

Your notice is about non-payment of paddy only and not about all the foodgrains.

कुंवर अखिलेश सिंह : खबी फसल की बुआई नहीं हुई है। किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं। पिछले वर्ा भारत सरकार ने 60 प्रतिशत चावल की रिक्वरी की थी। इस वर्ा उन्होंने 68 प्रतिशत चावल की रिक्वरी की। खरीद करने वाली सरकारी एजेंसियों का कहना है कि जो उत्तर प्रदेश में धान खरीद रहे हैं, उससे 68 प्रतिशत चावल पर लैवी देना सम्भव नहीं है। मेरी मांग है कि व्यावहारिक स्तर पर धान की खरीद जारी रखने के लिए जिस तरह पिछले वर्ा 60 प्रतिशत की रिक्वरी भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के लिए छूट में दी थी उसी तरह की रिक्वरी इस वर्ा करे अन्यथा उत्तर प्रदेश को 10 हजार करोड़ रुपए के विशेा पैकेज देने की घोाणा करे।